

सं-01/दि०स०नि०-UDID-01/2026 स.क.- 88

बिहार सरकार
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय
(समाज कल्याण विभाग)

28/01/26

15
2-27

बन्दना प्रेयषी, भारत
सचिव,
समाज कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव,
बिहार, पटना।

विषय:- यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (UDID) एवं दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के सत्यापन एवं दुरुपयोग की रोकथाम के संबंध में।

प्रसंग:- संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक-P13013/23/2021-UDID (Part-3) दिनांक-24.11.2024

महोदय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासांगिक पत्र के आलोक में अंकित करना है कि यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (UDID) कार्ड/दिव्यांगता प्रमाण-पत्र दिव्यांग व्यक्तियों को राज्य एवं केंद्र सरकारों द्वारा अधिसूचित विभिन्न लाभ प्राप्त करने हेतु प्राथमिक एवं प्रामाणिक दस्तावेज है। यूडीआईडी कार्ड/दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के पात्र धारक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, सहायक उपकरणों की उपलब्धता, शिक्षा, रोजगार, परिवहन रियायतें, पुनर्वास तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु, कतिपय मामलों में जाली या फर्जी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एवं यूडीआईडी कार्ड जारी करने तथा उपयोग करने की घटनाएँ संज्ञान में आई हैं। उक्त के आलोक में संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एडवाइजरी (संलग्न) करते हुए अंकित किया गया है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अध्याय-16 (अपराध एवं शास्तियां) की विभिन्न धाराओं में ऐसे कृत्यों/अपराधों के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया गया है जो निम्नलिखित हैं: -

(क) अधिनियम की धारा-89 के अनुसार, कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है, पहले उल्लंघन के लिए जुर्माने से जो ₹10,000/- तक हो सकेगा तथा पुनरावृत्ति पर ₹50,000/- से ₹5,00,000/- तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

(ख) अधिनियम की धारा-91 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित किसी लाभ को धोखाधड़ी से प्राप्त करता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसे दो वर्ष तक का कारावास या अधिकतम ₹1,00,000/- का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

उप सचिव

मुख्यालय (स्थापना)

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

आयरी संख्या-168

दिनांक-30-01-26

Comp-5/10/Office Work/Sec. Letter

AS
D/S-01

30-01-26

प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना
आयरी सं०-669
दिनांक-28/01/26

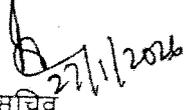
अपर सचिव, कोषांग
आयरी सं०-950
दिनांक-29.01.2026
जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना

30-01-26

49
02/02/28

अतः उक्त के आलोक में अनुरोध है कि अपने-अपने विभाग अंतर्गत नियुक्ति या प्रवेश प्रदान करने से पूर्व संबंधित चिकित्सा प्राधिकरण या नामित अस्पताल से यूडीआईडी कार्ड/दिव्यांगता प्रमाण-पत्र का सत्यापन कराने हेतु संबंधित भर्ती एजेंसियों/संस्थाओं को निर्देशित करने की कृपा की जाए।

अनु०-यथोक्त।

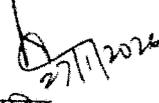

27/1/2026
सचिव

समाज कल्याण विभाग
बिहार, पटना

जापांक-01/दि०स०नि०-UDID-01/2026 स.क.- 88 पटना, दिनांक- 28/01/26

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, आई.सी.डी.एस. निदेशालय/ निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/ निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, एस.एस.यू.पी.एस.डब्ल्यू. सक्षम, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. सभी सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. सभी सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अपने-अपने जिला अंतर्गत दिव्यांगजनों को जारी एडवाइजरी में निहित सलाहों/प्रावधानों के संबंध में जागरूक करना सुनिश्चित करेंगे।


27/1/2026
सचिव

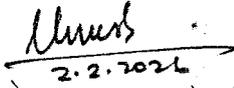
समाज कल्याण विभाग
बिहार, पटना

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

जापांक-17/विविध(बाह्य)-04-05/2025-

/पटना, दिनांक-

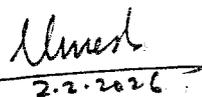
प्रतिलिपि :-अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)/सभी मुख्य अभियंता/उप सचिव प्रभारी प्रशाखा-01/02/03/04/05 एवं 09, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


2.2.2026
(उमेश प्रसाद गुप्ता)
सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक-17/विविध(बाह्य)-04-05/2025-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :-कार्यपालक अभियंता, सूचना प्रवैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड/ई-मेल करने हेतु प्रेषित।


2.2.2026
(उमेश प्रसाद गुप्ता)
सरकार के संयुक्त सचिव

प्रेषक,

बन्दिना प्रेयषी, भा.प्र.से.
सचिव,
समाज कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव,
बिहार, पटना।

विषय:-

यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (UDID) एवं दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के सत्यापन एवं दुरुपयोग की रोकथाम के संबंध में।

प्रसंग:-

संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक-P13013/23/2021-UDID (Part-3) दिनांक-24.11.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासांगिक पत्र के आलोक में अंकित करना है कि यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (UDID) कार्ड/दिव्यांगता प्रमाण-पत्र दिव्यांग व्यक्तियों को राज्य एवं केंद्र सरकारों द्वारा अधिसूचित विभिन्न लाभ प्राप्त करने हेतु प्राथमिक एवं प्रामाणिक दस्तावेज है। यूडीआईडी कार्ड/दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के पात्र धारक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, सहायक उपकरणों की उपलब्धता, शिक्षा, रोजगार, परिवहन रियायतें, पुनर्वास तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु, कतिपय मामलों में जाली या फर्जी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एवं यूडीआईडी कार्ड जारी करने तथा उपयोग करने की घटनाएँ संज्ञान में आई हैं। उक्त के आलोक में संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एडवाइजरी (संलग्न) करते हुए अंकित किया गया है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अध्याय-16 (अपराध एवं शास्तियां) की विभिन्न धाराओं में ऐसे कृत्यों/अपराधों के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया गया है, जो निम्नलिखित हैं: -

(क) अधिनियम की धारा-89 के अनुसार, कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है, पहले उल्लंघन के लिए जुर्माने से जो ₹10,000/- तक हो सकेगा तथा पुनरावृत्ति पर ₹50,000/- से ₹5,00,000/- तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

(ख) अधिनियम की धारा-91 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित किसी लाभ को धोखाधड़ी से प्राप्त करता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसे दो वर्ष तक का कारावास या अधिकतम ₹1,00,000/- का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

12

अतः उक्त के आलोक में अनुरोध है कि अपने-अपने विभाग अंतर्गत नियुक्ति या प्रवेश प्रदान करने से पूर्व संबंधित चिकित्सा प्राधिकरण या नामित अस्पताल से यूडीआईडी कार्ड/दिव्यांगता प्रमाण-पत्र का सत्यापन कराने हेतु संबंधित भर्ती एजेंसियों/संस्थाओं को निर्देशित करने की कृपा की जाए।

अनु०-यथोक्त।

27/1/2024

सचिव

समाज कल्याण विभाग

बिहार, पटना

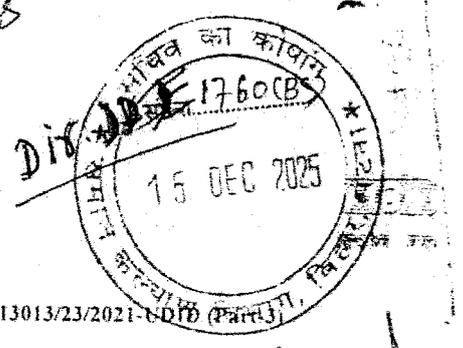
534

8652
15-12-25

EX 042708 (97) IN

22

Rajeev Sharma
Joint Secretary

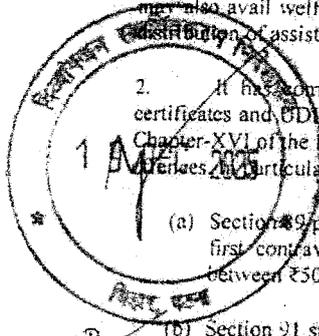


Ministry of Social Justice & Empowerment
Department of Empowerment of Persons with Disabilities

D.O. No.: P-13013/23/2021-UDID (Part III)

Dated : 24th November, 2025

The *Unique Disability ID (UDID) Card* and *Disability Certificate* serve as the primary and authentic documents enabling persons with disabilities to avail various benefits notified by the Central and State/UT Governments. Eligible holders of UDID cards and disability certificates can apply for employment and admission in higher educational institutions operated by or receiving aid from the competent government. They may also avail welfare schemes such as pension, transport concessions, assistance in procurement of vehicles, distribution of assistive devices, and other applicable benefits.



2. It has come to notice that incidents of issuance and circulation of fraudulent or fake disability certificates and UDID cards have been reported from various States/UTs as well as by members of the public. Chapter-XVI of the Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act, 2016 prescribes stringent penalties for such offences as particular:

- (a) Section 89 provides that any person contravening any provision of the Act or related rules shall, for the first contravention, be liable to a fine up to ₹10,000 and for subsequent contraventions to a fine between ₹50,000 and ₹5,00,000.
- (b) Section 91 stipulates that any person who fraudulently avails or attempts to avail any benefit meant for persons with benchmark disabilities shall be punishable with imprisonment up to two years, or with fine up to ₹1,00,000 or with both.

3. In the interest of ensuring integrity and transparency in the delivery of benefits to *persons with disabilities*, this advisory is issued to all active UDID card and disability certificate holders to verify and validate their disability credentials before availing any benefits. This is essential not only to maintain the *safety* of the system but also to safeguard individuals from penalties under the Act in cases of misuse, whether intentional or inadvertent.

It is further requested that all Ministries/Departments of the Government of India, and the Social Welfare Departments of State/UT Governments dealing with disability-related matters, may kindly issue necessary instructions to recruiting agencies, higher educational institutions, and other implementing bodies under their administrative control or in the jurisdiction of respective State/UT administration. These agencies/institutions may be directed to authenticate the UDID card and disability certificate of applicants/beneficiaries with the issuing medical authority or designated hospital prior to granting any benefit, appointment, or admission. Additionally, revised advisory No. P-13013/95/2023-UDID/IT/Statistics dated 15th October be followed for the cases as mandated in the said advisory.

5. Your personal attention to this matter will greatly strengthen the credibility and reliability of disability-related service delivery mechanisms across the country.

Yours sincerely,

(Rajeev Sharma)

3657
22-12-2025

- 1. All Secretaries to the Government of India (As per standard list).
- 2. All principal Secretaries / Secretaries of social welfare department dealing with the subject of disability of all State/UTs (As per standard list).
- 3. All UDID related nodal officer in the State/UTs (Through website and UDID portal also).
- 4. All UDID and disability certificates holders in the country through website and UDID portal.

222

10

No. P-13013/95/2023-UDID/IT/STATISTICS

Govt. of India

Ministry of Social Justice & Empowerment

Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)

5th Floor, Pandit Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003

Date 15th October, 2025

CIRCULAR

Subject:- Revised Advisory and Standard Operating Procedure (SOP) to handle the cases of PwBD candidates applying for jobs or admission with Government Employers (GEs) or Government Institutions of Higher Education (GIHE) and Other Higher Education Institutions aided by Government (OHEI) regarding.

The undersigned is directed to refer to the subject mentioned above and to state that the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan) has issued a revised **Advisory and Standard Operating Procedure (SOP)** to handle cases of Persons with Benchmark Disabilities (PwBDs) applying for employment or admission with Government Employers (GEs), Government Institutions of Higher Education (GIHEs), and Other Higher Education Institutions (OHEIs) aided by Government.

2. The enclosed Advisory and SOP are issued in supersession of the earlier Advisory-cum-SOP circulated vide this Department's letter No. P-13013/95/2023-UDID/IT/STATISTICS dated 17.09.2024. All concerned authorities are requested to take necessary action for its implementation and ensure compliance.

3. This issues with the approval of the competent authority.

Encl: As above


(Manish Kumar Mishra)

Under Secretary to the Government of India

To,

1. All Secretaries of Government of India
2. Additional Chief Secretaries of Health/Principal Health Secretaries/Secretaries of Health Department/Directorate General of Health Services (All States/UTs Govt.)
3. Principal Secretaries of Social Welfare Department/Secretaries of Social Welfare Department/Director Social Welfare Department (All States/UTs Govt.)
4. Chairmen/Heads of all recruiting and examination bodies of Centre, State and UT Governments

Copy to:

1. Office of Chief Commissioner of Persons with Disabilities (CCPD), New Delhi
2. State Chief Commissioners of Persons with Disabilities (SCPDs) (All States/UTs Govt.)
3. Web manager, DEPwD with a request to upload on the website of the Dept. for wide publication


(Manish Kumar Mishra)



No. P-13013/95/2023-UDID/IT/STATISTICS
Government of India
Ministry of Social Justice & Empowerment
(Department of Empowerment of Persons with Disabilities)

Date: 15th October, 2025

Revised Advisory and Standard Operating Procedure (SOP) to handle the cases of PwBD candidates applying for jobs or admission with Government Employers (GEs) or Government Institutions of Higher Education (GIHE) and Other Higher Education Institutions aided by Government (OHEI) regarding.

Reference:

1. This department's gazette notifications dated 26.04.2016 and 04.01.2018 prescribing the disability assessment guidelines (SOP) for disability certification
2. Launch of UDID project through online swavalamban portal in January, 2017 vide Section 18(5) of RPwD Act, 2016
3. This department's Gazette Notification dated 21.05.2021 on mandatory issuance of certificate of disability through swavlambancard.gov.in portal.
4. Department's notification no: 38/16-2020/DDIII (Note 8) dated 4th January 2021 mandating the government employers to verify the authenticity of certificate of disability and examine suitability of the candidate in terms of functional requirement before appointment.
5. SOP on appeal for re-assessment of disability, issued by this DEPwD dated 19.06.2024
6. CCPD's order dated 05.03.2024 in Case No. 14380/1031/2023 directing MoH&FW, Gol to create a structure for handling the appeals of PwBD students, against the assessments of the designated medical boards of NMC.
7. Disability assessment guidelines (SOP) for disability certification, issued by department vide Gazette Notification dated 12.03.2024, and as amended from time to time.
8. Appeal mechanism prescribed by DEPwD for Government Employers (GEs) or Government and Other Institutions of Higher Education (GIHE& OHEI) dated 17.07.2024.
9. This department's communication to UPSC, vide letter no. 18-25/2024/policy dated 25.04.2025, authorizing any organization to verify disability status/suitability for job by conducting a medical test.

Section 32 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 provides for reservation of not less than five percent seats for persons with benchmark disabilities in all Government

[Handwritten signature]

Institutions of Higher Education (GIHE) and other Higher Education Institutions (OHEI) aided by the Government. Further, Section 34 of this Act also mandates the appropriate Government (GE) to appoint in every Government establishment not less than four percent of the total number of vacancies in the cadre strength in each group of posts, duly identified by the appropriate Government as mandated under Section 33 of the Act to be filled with persons with benchmark disabilities. It is essential that only genuine PwBD applicants meeting functional requirements of job/course get selected. This comprehensive SOP is being issued towards this goal only.

The stakes in the selection to above mentioned jobs and higher education courses are quite high and consequently the competition is equally fierce. Of late, there have been some complaints about getting a fake disability certificate or with a different or higher percentage than actual disability. The DEPwD therefore, in compliance of reference- 4 & 6 and in supersession of reference- 8, is issuing the present comprehensive guidelines (SOP).

1. **Ensuring that disability certificate is genuine:** The "Unique Disability ID (UDID)" project was launched in January, 2017 (reference-2) to create a National Database for all Persons with Disabilities (PwDs). Accordingly, certificates of disability and Unique Disability Identity cards are issued to Persons with Disabilities through medical assessment of PwDs (reference-1 & 7) by competent medical authorities notified by governments of respective States /Union Territories. It is pertinent to mention here that in RPwD Act, the number of disabilities were increased to 21 from the 7 disabilities mentioned in PwD Act, 1995.

Vide Rule-20 of RPwD Rules, 2017, the certificates of disability issued under the repealed PwD Act, 1995, shall continue to be valid after commencement of the RPwD Act, 2016 for the period specified therein. Vide Rule 18(5) of the same rules, the DEPwD mandated that, 01.06.2021 onwards, the disability certificate shall be generated only through the swavalamban portal. However, a provision was kept in the said portal for digitizing the manual disability certificates generated earlier under RPwD Act, 2016 or under PwD Act, 1995. Now, majority of this work is also complete.

Accordingly, all GEs/GIHEs/OHEIs are hereby requested to authenticate validity of disability certificate/UDID card from UDID portal. For this purpose, they are also encouraged to integrate their respective portals with UDID's national database through an API for real-time, authentic update on disability of individual applicants. UDID's API can be shared with GE/GIHE/OHEI by department under a standard process of MoU. Further. The

GEs/GIHEs/OHEIs are advised to instruct, through their job notification/admission guidelines, the applicants to get their manual certificate (if any) digitized on UDID portal well within time, for such API-based authentication. However, if a manual old disability certificate is presented by the candidate, it may be got validated by the corresponding issuing authority of the State Government.

2. Ensuring that Disability type and percentage of disability is correctly assessed and meets functional requirements of job/course

Presently, UDID card is issued to PwDs through a decentralized mechanism of medical examination in various district/sub-district hospitals as notified by respective state/UT governments. The disability assessment guidelines, issued vide reference-6 above, have been framed based on infrastructure, expertise and training available in various parts of country to carry out the disability assessment. However, it is possible that medical institutions/Hospitals/Medical Boards empanelled by GE/GIHE/OHEI may be better equipped in terms of tools, equipments, machines, technologies to have more accurate assessment of the disability using disability assessment guidelines issued by Department (DEPWD). Medical institutions/Hospitals/Medical Boards can therefore additionally use those tools, equipments, assessment while evaluating a candidate for disability for jobs or admission with GE/GIHE/OHEI.

It is also pertinent to mention that disability assessment guidelines have been framed to establish extent of disability in an individual and does not necessarily provide assurance of fitness of individual for a particular job or educational curriculum requirements. Therefore, many GE/GIHEs/OHEIs may additionally examine the PwBD applicants medically to establish suitability of applicant for the course/post for which he/she is being considered by GE/GIHE/OHEI. If necessary set of information required to establish suitability of job/admission is not available in any of the 3 documents available in UDID database, viz., UDID card, Disability certificate and diagnostics sheet, the earlier referred appropriate tests/procedures/protocols may also be included in the process of medical examination by GE/GIHE/OHEI. It needs to be ensured that sufficient number of hospitals are empanelled across the country by the GE/GIHE/OHEI so that PwBD candidates do not have to travel too far.

3. Ensuring that an Appellate mechanism exists if PwBD is aggrieved by decision of empanelled hospital of GE/GIHE/OHEI

[Handwritten signature]

[Handwritten number]

		Lumsey, 5th Mile. Gangtok-737102, Sikkim	
31.	Tamil Nadu	Tmt. JAYASHREE MURALIDHARAN, I.A.S Secretary, Department of Welfare of Differently Abled Persons Govt. of Tamil Nadu, K. K. Nagar, Chennai-600078 Tamil Nadu	Tel: 044-25671545 Fax: 044-25675183 Email: swsec@tn.gov.in
32.	Telangana	Sri Anitha Ramchandran Secretary Department of Women, Children, Disabled and Senior Citizens Welfare Room No.3, 3 rd Floor, Telangana Secretariat, Telangana, Hyderabad - 500 022.	Tel: 040 - 23450034. Fax: 23450924 Email: secy-wcdsc@telangana.gov.in
33.	Tripura	Shri Tapas Ray, Secretary, Department of Social Welfare, Govt. of Tripura, Agartala-799001, Tripura.	Tel: 0381-2415706, 2418070 Email: secretaryswse010422@gmail.com
34.	Uttar Pradesh	Shri Pramod Kumar Upadhyay Principal Secretary, Department of Disabled Welfare, Govt. of Uttar Pradesh, Room No.732, 7th Floor, BhupuBhawan, Sachivalaya, Lucknow-226001, Uttar Pradesh.	Tel: 0522-2238063 Cell: Email: secretary.sw@dirsamajkalyan.in
35.	Uttarakhand	Dr. Sridhar Babu Addanki, IAS Secretary, Department of Social Welfare, Govt. of Uttarakhand, Dehradun, Uttarakhand.	Tel: 0135-2650612 Email: secretarysw.uk@gmail.com
36.	West Bengal	Ms. Sanghamitra Ghosh Principal Secretary, Department of Social Welfare, Govt. of West Bengal. Kolkatta-700001, West Bengal.	Tel: 033-23341563 Fax: 033-23341918 Email: seedsw@gmail.com

23.	Meghalaya	Shri. Israel W. Ingty. I.A.S. Secretary. Social Welfare Department, Govt. of Meghalaya, Main Secretariat Building, Room No. 230, Shillong-793001. Meghalaya.	Phone (O) :0364 2223580 - S2425 Email: dte_swmeq@yahoo.in , swdshillong@gmail.com
24.	Mizoram	Lalzarmawii, IAS Director, Commissioner & Secretary Department of Social Welfare, Govt. of Mizoram, Chaltlang Aizawl-796001, Mizoram.	Tel: 0389-2323215 Email: socdepmiz@gmail.com
25.	Nagaland	Smt. Martha R Ritse Commissioner & Secretary, Department of Social Welfare, Govt. of Nagaland , Kohima-797004.	Tel: 0370-2270279 Email: socialwelfaredepartment_nagaland@yahoo.com
26.	Odisha	Shri. R. S Gopalan, IAS Commissioner cum Secretary, Department of Social Security & Empowerment of Persons with Disabilities, Government of Odisha, SIDR Building, Capital Hospital Campus, Unit-6, Bhubaneshwar-751001 Odisha	Tel: 0674-2390116 Fax: 0674-2390117 Email: ssepdsec.od@nic.in
27.	Puducherry (UT)	Smt. R. Smitha, I.A.S.. (AGMU:2011) Secretary to Government (Labour) Department of Social Welfare & Personnel, Govt. of Puducherry , Puducherry-605001	Tel : +91-413-2344800, 2233347 E-Mail: secyhealth@py.gov.in secvlab@py.gov.in
28.	Punjab	Sh. Vikas Partap IAS, Additional Chief Secretary, Department of Social Security and Women & Child Development, Punjab.	Tel: 0172-2742920 Email: psss@punjab.gov.in
29.	Rajasthan	APARNA ARORA Additional Chief Secretary Department of Social Justice & Empowerment, Directorate of Specially Abled Person, Govt. of Rajasthan, Secretariat, Jaipur-302005 Rajasthan.	Tel: 0141-2227683 Email: ps-sje@rajasthan.gov.in
30.	Sikkim	Smt. Sarika Pradhan, IAS Secretary Social Justice, Empowerment & Welfare Department. Govt. of Sikkim , SamajKalyanBhawan.	Mobile No. 9434756998 Email: sikkimsocialwelfare@gmail.com

16.	Karnataka	Dr. Shamla Iqbal Secretary to Government, Department of Women and Child Development and Empowerment of Differently Abled and Senior Citizens Karnataka.	080-2203 2562, 080-2235 3991 Email: priseev-wc@karnataka.gov.in
17.	Kerala	Dr. Adeela Abdulla IAS Special Secretary, Social Justice Department, Government of Kerala, Room No. 620, 1st Floor, South Block, Secretariat, Trivandrum, Kerala - 695033.	Ph: 0471- 2517311 E-mail: socialjusticebdepartment@gmail.com 0
18.	Ladakh (UT)	Ms. Shashanka Ala. IAS. Secretary, Social & Tribal Welfare Department, Civil Secretariat, U.T. Ladakh-194101	E-mail: secretarypaladakh@gmail.com Contact No: 01982-258365
19.	Lakshadweep (UT)	Shri. Soma Sekhar Apparao Kotaru IAS Secretary, Department of Social Welfare, UT Administration of Lakshadweep, Kavaratti-682555, Lakshadweep	Phone No : 0489-6262264, 6262241 Email: lk-coll@nic.in ednesttutl@gmail.com
20.	Madhya Pradesh	Mrs. SONALI PONKSHE VAYANGANKAR (IAS) Principal Secretary, Department of Social Justice, Govt. of Madhya Pradesh, Room Number F004 Ground Floor, Vallabh Bhawan Bhopal, Madhya Pradesh-462004.	Tel: 0755-2550447 Email: pssocialjustice@mp.gov.in
21.	Maharashtra	Shri. Dr. Harshadeep Kamble (IAS) Principal Secretary, Social Justice & Special Assistance Department, Govt. of Maharashtra, 1st Floor, Annex Building, Mantralay, Madam Cama Road, HutatmaRajguru Chowk, Nariman Point, Mumbai - 400032 Office Ph: 022-22025251, 22028660	Tel: 022-22026688 Fax: 022-22836688, 22029526 Email: psec.socjustice@maharashtra.gov.in
22.	Manipur	Shri Ningthoujam Geoffrey, Commissioner-cum-Secretary, Department of Social Welfare, Govt. of Manipur, Directorate Complex AT Line (2nd MR Gate) Imphal, Manipur- 796001.	Tel: 0385-2450682, Email: principalsecretary.pv.ias@gmail.com

8.	Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu (UT)	Shri Ajay Kumar Gupta. IAS Secretary. SW & WCD Department of Social Welfare. UT Administration of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu Silvassa-396230, Dadra & Nagar Haveli	Tel: 0260-2632027 Email: secy-sw-dnda.gov.in
9	Delhi (UT)	Dr. Dilraj Kaur IAS Secretary, Department of Social Welfare, Government of NCT of Delhi, GNLS Complex, Delhi Gate, New Delhi-110001	Tel: 23490009 Fax: 23314819 Email: pssw@nic.in
10.	Goa	Shri Prasanna Acharya I.A.S Secretary, Empowerment of Persons with Disabilities Goa Legislative Assembly, Alto Porvorim, Bardez, Penha de Franc, Goa 403521.	Tel: 0832-2419409 Email: sec-fisheries@goa.gov.in
11.	Gujarat	Shri Mohammad Shahid, I.A.S. Principal Secretary Department of Social Justice & Empowerment Block No.-5, 9th floor, Sachivalay, Gandhinagar, Gujarat (India)	Tel: 079-23251203, 23251201, 2325120 Email: secswd@gujarat.gov.in
12.	Haryana	Dr. G. Anupama, IAS Additional Chief Secretary, Department of Social Justice & Empowerment, Govt. of Haryana, Room No. 621, 6th Floor, New Haryana Secretariat, Sector-17, Chandigarh-160017.	Tel: 0172-2543002 Mobile: Email: sjc@hry.nic.in
13.	Himachal Pradesh	Sh. Shyam Bhagat Negi Additional Chief Secretary 429, Armsdale Building, HP Secretariat, Shimla, H.P..	Tel: 0177-2621871 Email: socialjesecec-hp@nic.in
14.	Jammu & Kashmir	Mr. Mohammad Akhbar Wani (IAS) Director Department of Social Welfare, Govt. of Jammu & Kashmir, Civil Secretariat, Srinagar-171003,	Tel: 0194-2479645 Email: dirswkmr@gmail.com dirswkmr-jk@nic.in Fax: 0194-2506279
15.	Jharkhand	Shri Manoj Kumar, IAS Secretary, Department of Women Child Development & Social Security, Govt. of Jharkhand, Room No.304, Project Building, Dhurwa, Ranchi-834004. Jharkhand.	2400757, 2223544 Email: swdjharkhand@gmail.com

List of Social Welfare Secretaries of State/UTs

Sl. No.	State	Name & Address	☎
1.	Andaman & Nicobar Islands (UT)	Ravinder Kumar Secretary-Cum-Director Directorate of Social Welfare, Andaman and Nicobar Administration, Goalghar, Port Blair-744101	Tel: 03192-243817 Email: director-sw@and.nic.in
2.	Andhra Pradesh	Ms. G. Jaya Lakshmi Principal Secretary, Social Welfare Department, Government of Andhra Pradesh, 3rd Block, 1st Floor, Room No. 270, Andhra Pradesh Secretariat, Velagapudi, Hyderabad-500002, Andhra Pradesh	Tel: 0863-2443360 Email: peshi.wcdsc@gmail.com
3.	Arunachal Pradesh	Shri Abu Tayeng, IAS Secretary, Department of Women & Child Development, Social Justice & Empowerment & Tribal Affairs, Govt. of Arunachal Pradesh, Civil Secretariat, Itanagar, Room No.202, Block No. 2, 2 nd Floor, Itanagar-791111	Tel: 0360-2212311 Email: ar.sjeta@gmail.com
4.	Assam	Shri Pallav Gopal Jha, IAS Secretary, Department of Social Welfare, Govt. of Assam, B-Block, 3rd Floor, Assam Secretariat (Janata Bhawan), Dispur, Guwahati, Kamrup Metro, Assam, PIN-781006.	Tel: 0361-2237243 (Telefax) Email: pallavg.jha@ias.nic.in
5.	Bihar	Smt. Bandana Preyashi IAS. Special Secretary, Social Welfare Department, Govt. of Bihar, Old Secretariat Campus, Block No. 4, Patna. Bihar -800015	Tel: 0612- 2217244, 2280372 Fax: 0612- 2217239 Email: secysw-bih@nic.in , swbihar@gmail.com
6.	Chandigarh (UT)	Ms. Anuradha S. Chagti Secretary Social Welfare Department UT Administration of Chandigarh, Room No. 116, 1st Floor, U.T. Secretariat, Sector-9, Chandigarh	Tel: 0172-2749923 Email: sspersonneluti@gmail.com
7.	Chhattisgarh	Shri Bhuvnesh Yadav (I.A.S.) Secretary, Department of Social Welfare, Govt. of Chhattisgarh, Room No.S1- 15, Mahanadi Bhawan, Mantraluya, New Raipur,	Tel: 0771-2510088 Email: secy-sw.cg@gov.in secy.wcd-cg@nic.in

8/2/17

CCPD, vide reference-6 above, has also mandated for providing for Appellate hospitals by GE/GIHE/OHEI if the candidate has any grievance against the decision of the empanelled hospital. Therefore, an appeal arrangement is also expected to be provided by GE/GIHE/OHEI to PwBD applicants for re-evaluation of his suitability and extent of disability for the offered job/admission.

12

1/1